



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263457
CG-DL-E-29052025-263457

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]
No. 395]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/ज्येष्ठ 8, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISTA 8, 1947

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

फा.क्र: एएक्स1/एसटी/ओएसआर/01/2025-26.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण)

अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 4/2/1/2022-आईआर, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में किए गए या किए जाने से हटाए गए कार्यों को छोड़कर 1 नवंबर 2022 को और उस दिनांक से आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक, एतद्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकता है।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनकी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके उपरांत एतद्वारा उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 3 में -
(i) खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —
(एफ) चिकित्सा सुविधाओं और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी के "परिवार" का अर्थ होगा:
 - (i) अधिकारी की पत्नी/ पति
 - (ii) पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित);

- (iii) चालीस प्रतिशत या अधिक विकलांगता के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग पूरी तरह से आश्रित भाई या बहन
- (iv) विधवा वेटियां और आश्रित तलाकशुदा / परित्यक्ता वेटियां
- (v) बहनें जिनमें अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्ता / पति से अलग या विधवा बहनें शामिल हैं
- (vi) अधिकारी पर पूरी तरह से आश्रित माता-पिता

बशर्ते कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के मामले में, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उन्हें उनके विवाह के बाद भी आश्रित माना जाएगा यदि वे आश्रित के लिए आय संबंधी मानदंड को पूरा करते हैं।

स्पष्टीकरण 1 – “पूर्ण रूप से आश्रित सदस्य” का अर्थ परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी आय रु.18,000 प्रति माह से अधिक नहीं है। जहां परिवार के पूर्ण आश्रित सदस्य माता-पिता हैं तो माता-पिता में से किसी की भी आय या माता-पिता दोनों की कुल आय यदि रु.18,000 प्रति माह से अधिक है तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 – सभी अधिकारी कर्मचारियों, महिला या पुरुष, के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना और छुट्टी किराया रियायत के उद्देश्य से, आश्रित पिता, माता, ससुर, सास में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा और अधिकारी कर्मचारी के पास कैलेंडर वर्ष में एक बार आश्रितों में से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण 3 – यह परिभाषा 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी और कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, चिकित्सा बीमा योजना के उद्देश्य से, आश्रितों का संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में,

(क) उप-विनियम 7 का स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा।

(ख) उप-विनियम (8) और (9) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः

“(8) 1 नवंबर, 2022 को और उस दिन से प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रभावी निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹156500 – 4340/4 – 173860

वेतनमान VI = ₹140500 - 4000/4 – 156500

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020

वेतनमान IV = ₹102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹ 85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

वेतनमान II = ₹ 64820-2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹ 48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

स्पष्टीकरण — प्रत्येक अधिकारी, जो 31 अक्टूबर, 2022 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित है, को चरण-दर-चरण आधार पर 1 नवंबर, 2022 को इस उप-विनियम के अनुसार निर्धारित वेतनमान में अर्थात् संबंधित वेतनमानों में पहले चरण से आगे संबंधित चरणों में, फिट किया जाएगा और वेतन वृद्धि अन्यथा प्रावधान न होने पर हमेशा की तरह वर्षगांठ की तारीख पर दी जाएगी।

(9) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए वेतनमान निम्नानुसार होगा:

शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VIII = ₹ 253000 – 9000/4 - 289000

(10) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे:

वेतनमान I - III - मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV - V - मूल वेतन का 10 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VII - मूल वेतन का 11 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

(11) 1 नवंबर, 2017 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे:

वेतनमान I - III - मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV - V - मूल वेतन का 19 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VIII - मूल वेतन का 20 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

(12) 1 नवंबर, 2022 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे:

वेतनमान I - मूल वेतन का 26.50 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान II - III - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV - V - मूल वेतन का 30.50 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VII - मूल वेतन का 31.50 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

(13) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए विशेष भत्ता निम्नानुसार होगा:

विशेष भत्ता वेतनमान VIII = मूल वेतन का 28.30% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

नोट: उप विनियम (10) से (13) में संदर्भित विशेष भत्ते और उस पर लागू महंगाई भत्ते की विनिर्दिष्ट अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गणना नहीं की जाएगी।

(14) उप-विनियम (1) से (9) में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में सेवारत अधिकारी आवश्यक हैं।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में—

(क) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (8) के प्रावधानों के अध्यधीन, 1 नवंबर, 2022 को और उस दिन से, वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन दी जाएगी, अर्थात्:—

(क) विनियमन 4 के उप-विनियम (8) एवं (9) में निर्धारित वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर उपार्जित होगी तथा उस महीने के पहले दिन दी जाएगी, जिसमें यह देय है;

(ख) अपने संबंधित वेतनमान में अधिकतम स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अगले उच्च वेतनमान में अवरुद्ध वेतन वृद्धि सहित आगे की वेतन वृद्धि उनके दक्षता रोध को पार करने के अध्यधीन नीचे खंड (सी) और खंड (डी) में निर्दिष्ट अनुसार ही प्रदान की जाएगी;

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में अधिकारी, जो उच्च वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में अंतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों हेतु सात अवरुद्ध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो रु.2680/- प्रत्येक और अगली पांच रु.2980/- प्रत्येक होंगी।

बशर्ते कि अधिकारी पांचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, छठीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र हो;

बशर्ते यह भी कि अधिकारी पांचवीं अवरुद्ध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र हो।

(घ) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में अधिकारी, जो उच्च वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अंतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए रु.2980/- की सात अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी पांचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, छठीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र हो;

बशर्ते यह भी कि अधिकारी पांचवीं अवरुद्ध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र हो।

(ङ) मूलतः मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अधिकारी, अर्थात् वे जो मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में भर्ती किए गए हैं या पदोन्नत हुए हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के बाद पूरी की गई सेवा के प्रत्येक दो वर्षों के लिए आठ अवरुद्ध वेतन वृद्धि हेतु पात्र होंगे, जिनमें से पहली चार अवरुद्ध वेतन वृद्धि रु.2980/- प्रत्येक की होगी और अगली चार अवरुद्ध वेतन वृद्धि रु.3360/- प्रत्येक की होगी:

बशर्ते कि अधिकारी छठी अवरुद्ध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र हो।

बशर्ते यह भी कि अधिकारी छठी अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, आठवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र हो।

(च) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV के अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए पांच वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली वेतनवृद्धि रु.3360/- की होगी तथा अगली चार वेतनवृद्धियां रु.3680/- की होंगी।

बशर्ते कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, तीसरी वेतनवृद्धि के लिए पात्र हो।

बशर्ते कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022 को, जो जो भी बाद में हो, चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र हो।

बशर्ते कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि जारी होने के छह वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र हो।

(छ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए रु.4000/- की चार अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के चार वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, दूसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के छह वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, तीसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि अधिकारी अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के आठ वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

(ज) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी वेतनमान VI के अधिकारी, अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए तीन अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम दो अवरुद्ध वेतन वृद्धि रु.4000/- प्रत्येक की होगी तथा तीसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि रु.4340/- होगी:

बशर्ते कि अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, रु.4000/- की पहली अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, रु.4000/- की दूसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के छह वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, रु.4340/- की तीसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

(झ) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी वेतनमान VII के अधिकारी अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए रु.4340/- की तीन अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, पहली अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुके हैं, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, द्वितीय अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुके हैं, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के छह वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

नोट: इस उप-विनियम के खंड (ए) से (आई) में उल्लिखित वेतन वृद्धि/वृद्धियां उस अधिकारी को नहीं दी जाएंगी जो पदोन्नति का प्रस्ताव किए जाने पर उसे अस्वीकार कर देते हैं।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियां प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा तथा अधिकारियों के विशेषाधिकार, अनुलाभ, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पद के अनुसार जारी रहेंगी।

(ख) उप-विनियम (2) में, -

(i) स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित प्रोविज़ों अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 से सीएआईआईबी या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा (सीएआईआईबी-II) के भाग II को पूरा करने वाले अधिकारी जूनियर एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा (सीएआईआईबी-I) के भाग I को पूरा करने पर एक वेतन वृद्धि के अलावा अपने वेतनमान में दो वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि जो अधिकारी 1 नवंबर, 2022 तक बैंक की सेवाओं में थे और पहले ही सीएआईआईबी या सीएआईआईबी-II पूरा कर चुके हैं, वे 1 नवंबर, 2022 या सीएआईआईबी या सीएआईआईबी-II उत्तीर्ण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दूसरी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां किसी अधिकारी ने 8 मार्च, 2024 तक वेतनमान के अधिकतम स्तर (जेएआईआईबी या सीएआईआईबी के मामले में) पर पहुंचने के बाद या वेतनमान के अधिकतम स्तर से एक स्तर कम स्तर पर पहुंचने के बाद [सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) के मामले में] जेएआईआईबी या सीएआईआईबी-I या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) पहले ही प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करेगा और उसने ऐसी योग्यता हासिल करने के कारण अन्यथा हकदार वेतन वृद्धि अर्जित नहीं की है, जब उन कर्मचारियों के वेतनमान में प्रदान करने के लिए कोई वेतन वृद्धि नहीं थी, ऐसे मामलों में स्थिर वेतन वृद्धि एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, के लिए अग्रिम की जा सकती है।”

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (एच) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) 1 नवंबर, 2022 से, अन्य चीजें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित होगी, अर्थात्:-

तालिका

जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट (जेएआईआईबी) या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट I परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु. 1370/- प्रति माह।
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी-II) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों।	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद 1370/- रुपये प्रति माह। (ii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष बाद 3425/- रुपये प्रति माह; (iii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के तीन वर्ष बाद 5480/- रुपये प्रति माह;

बशर्ते कि वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने के दिनांक से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक

योग्यता वेतन की बाद की किस्तों का जारी करना ऐसी व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त को जारी करने के दिनांक के अनुसार होगी।"

(iii) नोट में, खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे:

"(vi) अधिकारी जो 1 नवंबर, 2022 तक बैंक की सेवाओं में थे और जिन्होंने पहले ही जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-1) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-2) पूरा कर लिया है और व्यावसायिक योग्यता वेतन-II प्राप्त कर रहे हैं, वे व्यावसायिक योग्यता वेतन-II जारी होने के एक वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022 से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक योग्यता वेतन-III के लिए पात्र होंगे।

(vii) अधिकारी जिन्होंने जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-1) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-2) पूरा कर लिया है और 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले वेतनमान में अधिकतम तक पहुंच गए हैं और 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले पहली ठहराव वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं की है, वे 1 नवंबर, 2022 से व्यावसायिक योग्यता वेतन-I के लिए पात्र होंगे और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्त की रिहाई इस खंड के अंतर्गत व्यावसायिक योग्यता वेतन I की रिहाई की तारीख के संदर्भ में होगी।

(viii) स्केल VIII के अधिकारी व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए पात्र नहीं होंगे और यह वेतन पर्ची (पे स्लिप) घटकों का हिस्सा नहीं होगा।"

(ग) उप-विनियम (3) में, -

(i) खंड (जी) के बाद का नोट हटा दिया जाएगा;

(ii) खंड (जी) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"(एच) 1 नवंबर, 2022 से, अन्य चीजें समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ निर्धारित वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा: -

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	01.11.2022 को वेतनवृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	बैंक द्वारा सुविधा प्रदान किये जाने पर देय कुल निश्चित वैयक्तिक वेतन (रु.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610

3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663

(i) अन्य चीजें समान होने पर, शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए मकान किराया भत्ते के साथ-साथ निश्चित वैयक्तिक वेतन नीचे दी गई तालिका में दी गई दरों पर होगा और पूरी सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा: -

तालिका

वेतन वृद्धि घटक(रु.)	वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता(रु.)	कुल देय नियत वैयक्तिक वेतन जहां बैंक का आवासीय सुविधा दी गई है। (रु.)
(1)	(2)	(3)
9000	669	9669.

नोट:

(क) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) (जी) (एच) और (आइ) में तालिकाओं के कॉलम (3) के अंतर्गत दर्शाया गया नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ख) आवास किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन, खंड (ज) के अधीन पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी तथा संबंधित अधिकारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त आवास किराया भत्ता होगा;

(ग) केवल वही अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में हैं, वे अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष उपरांत नियत वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।

(घ) 1 नवंबर, 1999 से, निश्चित वैयक्तिक वेतन जारी होने के कारण उप-विनियमन (2) के स्पष्टीकरण के खंड (सी) के अनुसार पेशेवर योग्यता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई बदलाव नहीं होगा:

बशर्ते कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी किए जाने के लिए निर्धारित है, वह अधिकारी को उस दिनांक को और उस दिनांक से तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।

(ङ) नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन का वेतनवृद्धि घटक अधिवर्षिता लाभों के लिए मान्य होगा।

(च) कोई अधिकारी जिसने इस उप-विनियम के खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि अर्जित की है, उन्हें वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष के उपरांत उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) या (आइ) में उल्लिखित 'नियत' वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन प्राप्त होगा।

5. विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(7) विनियम 6 के उपबंधों के अधीन, नियत तिथि को बैंक में अधिकारियों के विभिन्न पदों को नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

तालिका

पद	श्रेणी या वेतनमान जिसमें रखा गया
(1)	(2)
मुख्य महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी – स्केल VIII
महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी – स्केल VII
उप महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी – स्केल VI
सहायक महाप्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी – स्केल V
मुख्य प्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी – स्केल IV
वरिष्ठ प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी – स्केल III
प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी – स्केल II
उप प्रबंधक	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी – स्केल I

बशर्ते कि उपर्युक्त वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई और विसंगति को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर बनी समिति को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाए, निर्णय हेतु भेजा जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 21 में:

(क) स्पष्टीकरण: खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(बी) विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) में स्पष्टीकरण के अनुसार खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी) और (एच) में निर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन महंगाई भत्ते के लिए रैंक करेगा।”

(ख) उप-विनियम (7) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उप-विनियम (8) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(8) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से

(क) महंगाई भत्ता सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिंदु पर वेतन का 1% देय होगा।

(ख) उपर्युक्त तरीके से महंगाई भत्ते का भुगतान औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2016=100 के तिमाही औसत में 123.03 अंक से अधिक की वृद्धि या गिरावट के प्रत्येक परिवर्तन के लिए किया जाएगा। 123.03 अंकों से आगे सीपीआई 2016 के प्रत्येक दूसरे दशमलव स्थान पर परिवर्तन के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01% परिवर्तन होगा।

(ग) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन तिमाही आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को निम्नलिखित के आधार पर जारी किया जाएगा:

महंगाई भत्ते जारी का दिनांक	महीनों के सीपीआई अंकों का तिमाही औसत	माह के लिए लागू
1 मई	जनवरी, फरवरी और मार्च	मई, जून और जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई और जून	अगस्त, सितंबर और अक्टूबर
1 नवंबर	जुलाई, अगस्त और सितंबर	नवंबर, दिसंबर और जनवरी
1 फरवरी	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर	फरवरी, मार्च और अप्रैल

(घ) महंगाई भत्ते की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(ङ) त्रैमासिक औसत निकालते समय केवल पहले दो दशमलवों पर ही विचार किया जाएगा।”।

7. उक्त विनियमों के विनियम 22 में उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

‘(1) 1 नवम्बर, 2022 को और उसके बाद से,—

(क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है, वहां उन्हें वेतनमान के पहले चरण, जिसमें वह पदस्थ हैं, में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(ग) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है, वहां वे निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होंगे, अर्थात्:-

तालिका

कार्य स्थल	आवास किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) शूप ए में प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर और परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 10.0%
(ii) क्षेत्र 1 में अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 9.0 %
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 8.0 %

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें देय आवास किराया भत्ता उनके द्वारा अपने वेतनमान, जिसमें वह पदस्थ है, के पहले चरण के 0.35% से अधिक प्रदत्त वास्तविक किराया या उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित उपरोक्त दरों के अनुसार देय आवास किराया भत्ता के अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

नोट:- अधिकारियों के आवास किराया भत्ता के दावे उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े हैं जो अब आवास किराया भत्ता के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

8. उक्त विनियमों के विनियम 23 में, —

(क) उप-विनियम (1) और (2) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवारत हैं, तो उस स्थान के समक्ष कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा: —

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) क्षेत्र 1 और उससे ऊपर के स्थान और गोवा राज्य	रु. 2300/- प्रति माह
(ii) पांच लाख और उससे अधिक की आवादी वाले स्थान तथा राज्य की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर।	रु. 1900/- प्रति माह

(2) 1 नवंबर, 2022 से विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।

बशर्ते कि जहां अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट किसी स्थान पर उप-विनियम (10) के अंतर्गत प्रदत्त पर्वतीय एवं ईंधन भत्ता भी देय है, वहां अधिकारी दोनों भत्तों में से केवल उच्चतर भत्ता लेने का पात्र होगा, दोनों नहीं।"

बशर्ते कि दोनों भत्तों में से उच्चतर भत्ता, अधिकारी द्वारा 31 दिसम्बर, 1989 को आहरित विशेष भत्ते और पर्वतीय एवं ईंधन भत्ते के योग से कम हो, तो ऐसा अंतर तब तक वैयक्तिक भत्ते के रूप में संरक्षित रहेगा, जब तक अधिकारी उस स्थान पर रहता है।"

(ब) उप-विनियम (4), (5), (6) और (7) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियमों को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह अधिकतम दो बच्चों के संबंध में बाद वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक रु.2500/- प्रति माह मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा।

परंतु यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना बंद कर देते हैं तो यह भत्ता बंद हो जाएगा।

(5) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त है, तो वह उस पद, जिस पर वह प्रतिनियुक्त है, से जुड़ी परिलक्षियों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.7500 प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है, जो उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर प्राप्त करता:

परंतु यदि उसे किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो उसी स्थान या बैंक के गैर- स्वामित्व वाले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पर स्थित है, जिस स्थान पर या बैंक के गैर- स्वामित्व वाले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में उसकी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले उसकी तैनाती थी, तो उसे अपने वेतन का 4 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो अधिकतम रु.3750/- प्रतिमाह होगा:

जहां किसी अधिकारी को समान महानगरीय/ प्रमुख ए श्रेणी के शहरी समूह/ नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी अन्य कार्यालय/ शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है, जहां ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा/ कार्यालय से 20 किलोमीटर और उससे अधिक है, तो वह विनियम 41 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित विराम भत्ते के लिए पात्र होगा।

(6) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को उच्चतर वेतनमान के किसी पद पर एक ही समय में लगातार कम से कम चार दिन या एक कैलेंडर माह के दौरान कुल मिलाकर चार दिन की निरंतर अवधि के लिए स्थानापन्न होना पड़ता है, तो उसे अपने मूल वेतन के 15% के बराबर स्थानापन्न भत्ता, उस अवधि के लिए आनुपातिक रूप से प्राप्त होगा, जिसके लिए वह स्थानापन्न कार्य करता है। स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में गिना जाएगा।

परंतु, जहां कोई अधिकारी विनियम 6 के अंतर्गत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न कार्य करने के लिए आता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, अधिकारी प्रत्येक लेखाबंदी के लिए प्रति तिमाही रु.1500/- के लेखाबंदी भत्ते के लिए पात्र होंगे।”;

(ग) उप-विनियम (10), (11), (12) और (13) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियमों को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, अधिकारी नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट पर्वतीय और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्: —

सारणी

स्थान (1)	दर (2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई वाले स्थान लेकिन 1500 मीटर से कम और मर्कारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु.1450/- प्रति माह के अध्यधीन
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु.1900 प्रति माह के अध्यधीन
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.3750 प्रति माह के अध्यधीन

"(11) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, अधिकारी रु.850/- प्रतिमाह के शैक्षणिक भत्ते तथा उस पर महंगाई भत्ते के लिए पात्र होगा।"

नोट: अध्ययन भत्ते के साथ उस पर लागू महंगाई भत्ते की गणना सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् ग्रेच्युटी, पीएफ और परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) सहित पेंशन के लिए नहीं की जाएगी।

(12) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से ऐसे अधिकारी जो नगर प्रतिपूरक भत्ते (सीसीए) के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं, रु.1200/- प्रतिमाह के निश्चित स्थानीय भत्ते के लिए पात्र होंगे जिसे महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए परिकलित नहीं किया जाएगा।

(13) (ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 से सभी अधिकारी कर्मचारियों को बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार निम्नलिखित चयनित मानदंडों के आधार पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) देय होगा:

(i) चालू खाता बचत खाता - कासा (ii) गैर-निष्पादित आस्तियां - एनपीए (iii) विशेष उल्लिखित खाते -एसएमए (iv) गैर-ब्याज आय - एनआईआई (v) कुल कारोबार (vi) लाभप्रदता (ii) आस्तियों पर आय - आरओए अथवा इक्कीटी पर आय - आरओई (viii) सरकारी योजनाएं।

(बी) कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन - पीएलआई राशि 0-15 (अधिकतम) वेतन दिवसों (मूल+ महंगाई भत्ता) में देय होगी, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा खंड (क) में उल्लिखित निर्धारित मानदंडों पर निर्भर होगी।

9. उक्त विनियमों के विनियम 24 में,

(ए) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

“(1)” 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, एक अधिकारी स्वयं अपने और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जो अधिकारी के स्वयं के प्रमाण पत्र के आधार पर इस तरह के व्यय के लिए दावा की गई राशि के लिए खातों के विवरण द्वारा समर्थित हो, जैसा कि नीचे तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन श्रेणी	रु.13000/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु.15400/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि जो भी कम हो

नोट 1 :- किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता राशि संचित करने की अनुमति दी जा सकती है। जो किसी भी समय ऊपर प्रदान की गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए;

नोट 2 :- कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति राशि को दो महीनों, यानी नवंबर, 2022 और दिसंबर, 2022 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।;

(बी) उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-:

“(4) सभी अधिकारी कर्मचारी नेत्र जांच के लिए प्रति वर्ष रु.500/- की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे।

10. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी तथ्य के बावजूद, 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, बैंक के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह किसी अधिकारी, जो उस वेतनमान जिसमें वह पदस्थ है, के पहले चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत की राशि के बराबर या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा।

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर प्रदान किया जाता है, वहां बैंक द्वारा उस वेतनमान, जिसमें वह पदस्थ है, के पहले चरण में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी :

बशर्ते यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वहां बिजली, पानी, गैस और वातावरण संरक्षण (कंजर्वेन्सी) का खर्च अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।”

11. उक्त विनियमों के विनियम 31 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा”

“बशर्ते कि जहां मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अधिकारी को छुट्टी देने से इंकार किया जाता है या उसे स्थगित किया जाता है, तो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा उसके कारण का लिखित उल्लेख किया जाएगा।”

12. उक्त विनियम के विनियम 32 में उप-विनियम (3) को इस प्रकार जोड़ा जाएगा:

“(3) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक वर्ष में चार अवसरों पर आधे दिन के लिए दो दिन की आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए पात्र होगा, जिसमें से दो अवसर सुबह और दो अवसर दोपहर में होंगे।

बशर्ते कि इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक छुट्टी का लाभ 24 घंटे पहले आवेदन करने के बाद लिया जा सकेगा।

बशर्ते कि शेष बचे आकस्मिक छुट्टी को न ली गई आकस्मिक छुट्टी खाते में समाविष्ट करने के दौरान, शेष में अपूर्णांक, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।”

13. उक्त विनियमों के विनियम 33 में,—

(ए) उप-विनियम (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

“(4) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, विशेषाधिकार छुट्टी अधिकतम दो सौ सत्तर दिनों तक संचित किया जा सकेगा, सिवाय इसके कि छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण अधिकतम दो सौ पचपन दिनों तक सीमित होगा :

बशर्ते कि यह भी प्रावधान है कि कोई अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिनों की दर से विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा और यदि किसी अधिकारी की आयु पचपन वर्ष या उससे अधिक है, तो वह अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के लिए पात्र होगा।”

“(5) विशेषाधिकार छुट्टी लेने के इच्छुक अधिकारी को सामान्यतः छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के अतिरिक्त ऐसी छुट्टी लेने की अपनी इच्छा की सूचना कम से कम दस दिन पहले देनी होगी।

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार छुट्टी लेने हेतु 10 दिनों की कोई अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे :-

“(7) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, विशेषाधिकार छुट्टी की गणना के उद्देश्य से, आकस्मिक छुट्टी और अनिवार्य छुट्टी के अतिरिक्त सभी प्रकार की छुट्टी को शामिल नहीं किया जाएगा।”

14. उक्त विनियम के विनियम 34 में,

(ए) उप-विनियम (1) में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया जाएगा:

“बशर्ते कि 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, अधिकारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने की दर से बीमारी छुट्टी के लिए पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि अधिकारी की संपूर्ण सेवा में बीमारी छुट्टी (विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त बीमारी छुट्टी सहित) की कुल संख्या सात सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी।

(बी) उप-विनियम (5) के पश्चात उप-विनियम (6), (7) (8) और (9) को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:-

“(6) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, एकल पुरुष अभिभावक कर्मचारी अपने 8 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन बीमारी छुट्टी ले सकता है।

(7) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, महिला कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रति माह एक दिन की बीमारी छुट्टी ले सकती है।”

(8) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, अधिकारी कर्मचारी अपने 15 वर्ष या उससे कम आयु के विशेष बच्चे की बीमारी के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर बीमारी छुट्टी ले सकते हैं।

(9) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, अट्टावन वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिकारी कर्मचारी, कार्यस्थल के इतर किसी अन्य स्थान पर अपने पति/पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए बीमारी छुट्टी ले सकते हैं।

15. उक्त विनियम (1) के विनियम 36 में,

(ए) उप-विनियम (ए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(1)(ए) कोई महिला कर्मचारी किसी एक अवसर पर अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए तथा अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम बारह महीने के लिए वास्तविक वेतन पर मातृत्व छुट्टी के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में, मातृत्व छुट्टी की अवधि आठ महीने होगी :

1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, एक प्रसव में दो या अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व छुट्टी की अवधि बारह महीने होगी।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि मातृत्व छुट्टी आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़कर लिया जा सकता है।

(बी) उप-विनियम (डी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(डी) एक महिला कर्मचारी एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन छुट्टी ले सकती है: -

(ए) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी।

(बी) एक बच्चे को उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गोद लेना होगा और कर्मचारी ऐसी छुट्टी की मंजूरी के लिए बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करेगी।

(सी) बायोलॉजिकल माँ को भी उन मामलों में छुट्टी उपलब्ध होगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो।

(डी) सेवा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान 12 महीने की समग्र पात्रता के भीतर छुट्टी प्राप्त की जाएगी।

(सी) उप - विनियम (ई) को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

“(एफ) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, इन विट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) के लिए बारह महीने की समग्र सीमा के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन मातृत्व छुट्टी प्राप्त की जा सकती है।

(जी) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, शिशु के मृत जन्म लेने या जन्म के अट्राईस दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में महिला कर्मचारी द्वारा साठ दिनों तक विशेष मातृत्व प्राप्त की जा सकती है।”

16. उक्त विनियमन के विनियमन 37ए के लिए निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“37ए. विशेष आकस्मिक छुट्टी एवं विशेष छुट्टी – (1) 1 नवंबर 2020 को और उसके बाद से, अधिकारी कर्मचारी उन अवसरों पर विशेष आकस्मिक छुट्टी के लिए पात्र होंगे, यदि जिस शाखा में अधिकारी काम कर रहे हैं या जिस स्थान पर वह रह रहे हैं, वह कर्फ्यू, दंगों, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि से प्रभावित हो जाते हैं।

(2) 1 नवंबर 2020 को और उसके बाद से, शारीरिक/ आर्थोपेडिक रूप से विकलांग अधिकारी 04 दिनों के विशेष आकस्मिक छुट्टी के लिए पात्र होंगे।

(3) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, अखिल भारतीय अधिकारी संघ/एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में पञ्चीस दिनों तक की विशेष छुट्टी प्रदान की जाएगी।

(4) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, जो अधिकारी विभागीय जांच में बचाव प्रतिनिधि रहते हैं, वे अधिकारी कर्मचारी का बचाव प्रस्तुतीकरण तैयार करने के उद्देश्य से एक दिन की विशेष छुट्टी ले सकते हैं।

बशर्ते कि ऐसी विशेष छुट्टी एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों के लिए ली जा सकेगी।

(5) किसी अधिकारी को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा कोई विशेष छुट्टी भी प्रदान की जा सकती है।"

17. उक्त विनियमन के विनियमन 37ए के लिए निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'37वी. शोक छुट्टी - किसी अधिकारी कर्मचारी को उसके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता और सास-ससुर) की मृत्यु पर निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार शोक छुट्टी प्रदान की जाएगी।

बशर्ते कि छुट्टियों के बीच के अवकाश भी छुट्टी का हिस्सा होंगे।

बशर्ते कि उक्त छुट्टी का उपयोग मृत्यु के अधिकतम 15 दिन के भीतर किया जाए।

बशर्ते कि उक्त छुट्टी को विशेषाधिकार छुट्टी की गणना के प्रयोजनार्थ "सक्रिय सेवा" में नहीं माना जाएगा।'

18. उक्त विनियम के विनियम 41 में:

(क) उक्त विनियमों के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद, जब भी कभी किसी अधिकारी को कार्यालयीन कार्य से यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:—

(अ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी राजधानी अथवा शताब्दी अथवा तेजस अथवा वंदे भारत अथवा अमृत भारत प्रीमियम रेलों सहित किसी भी रेल (लग्जरी रेलों को छोड़कर) की प्रथम श्रेणी में यात्रा करने हेतु पात्र हैं: बशर्ते कि वे, हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकते हैं, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं या जन हित को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान की गई हो;

(आ) मध्यम प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी ऊपर दिए गए खण्ड (क) में उल्लिखित प्रीमियम रेलों सहित किसी भी रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा करने हेतु पात्र हैं।

बशर्ते कि वे हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकते हैं, यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो,

बशर्ते यह भी कि वे कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकते हैं, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं या जन हित को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान की गई हो:

(इ) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी ऊपर दिए गए खण्ड (क) में उल्लिखित रेल की एसी प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा करने हेतु पात्र हैं;

(ई) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी हवाई जहाज या रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:

बशर्ते कि, जब दो स्थानों के बीच की दूरी का एक प्रमुख हिस्सा हवाई जहाज या रेल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, तभी शेष दूरी सामान्यतः कार द्वारा तय की जानी चाहिए;

(उ) व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी अपने वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है;

(ऊ) किसी भी श्रेणी या वेतनमान का अधिकारी सड़क या हवाई जहाज या रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच यात्रा करने के लिए जल परिवहन के डिलक्स केबिन श्रेणी में यात्रा करने हेतु पात्र होंगे;

(ऋ) अधिकारी प्रीमियम रेलों (लग्जरी रेलों को छोड़कर) के किराए हेतु पात्र होंगे।

नोट 1: रेल किराये पर लगाया जाने वाला जीएसटी प्रभार पात्रता के अतिरिक्त होगा।

नोट 2: प्रचलित गतिशील किराया प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, बुकिंग की तिथि पर लिए गए रेल टिकटों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ख) उप-विनियम (4) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

‘4 (क) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित श्रेणी या वेतनमान के अधिकारी उसके तदनुरूपी कॉलम (2) में निर्धारित संबंधित दरों पर “प्रतिदिन” विराम भत्ते हेतु पात्र होंगे, अर्थात्:—

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी या वेतनमान	विराम भत्ता			
	महानगरीय रु.	प्रमुख 'ए' वर्ग के शहर रु.	क्षेत्र । रु.	अन्य स्थान रु.
(1)	(2)			
वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
वेतनमान IV और V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
वेतनमान I, II और III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किन्तु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों से आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण- विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" से तात्पर्य चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद का कोई हिस्सा होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से और

अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से तात्पर्य आठ घंटे से कम नहीं की अवधि होगी।"

(ख) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में दिए गए श्रेणी या वेतनमान के अधिकारी को भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में एकल कमरे के आवास शुल्क तक सीमित वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जो नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में दिए गए तदनुरूपी स्टार श्रेणी के हैं:

अधिकारियों की श्रेणी	ठहरने की पात्रता
(1)	(2)
वेतनमान - VI, VII and VIII	* होटल
वेतनमान - IV and V	* होटल
वेतनमान - II and III	* होटल (गैर-एसी)
वेतनमान - I	* होटल (गैर-एसी)

बशर्ते कि बोर्ड, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऊपर निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति निर्धारित कर सकता है।'

19. उक्त विनियमों के विनियम 42 में:

(क) उप-विनियम (2) में, खंड (i) में, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि 17 मार्च, 2023 से, स्थानांतरण पर एक अधिकारी को अपने व्यक्तिगत सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसके व्यय की प्रतिपूर्ति यह विचार करते हुए की जाएगी कि निम्नलिखित सीमाओं तक शिपमेंट केवल लॉरी के माध्यम से हो रहा है:

वेतन सीमा	जहां अधिकारी का परिवार है	जहां अधिकारी का कोई परिवार नहीं है
48480-64820	3000 किलोग्राम या 3 टन	1500 किलोग्राम या 1.5 टन
64821 और उससे अधिक	12000 किलोग्राम या 12 टन	2500 किलोग्राम या 2.5 टन

बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:

दूरी किलोमीटर में	संशोधित दर रूपये प्रति किलोमीटर में
1000 किलोमीटर तक	रु. 5.90/-
1000 किलोमीटर से आगे	रु. 4.25/-

नोट 1:- उपरोक्त दरें स्लैब के आधार पर लागू होंगी, अर्थात्, पहले 1000 किलोमीटर के लिए, लागू दर ₹5.90/- प्रति किलोमीटर होगी और उसके बाद यह ₹4.25/- प्रति किलोमीटर होगी।

नोट 2:- 300 किलोमीटर तक की छोटी दूरी पर स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों के मामले में, 300 किलोमीटर तक प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है।

नोट 3:- पर्वतीय इलाकों से स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों के मामले में, उन्हें पर्वतीय इलाकों में तय की गई दूरी के लिए लागू दर का दो गुना और शेष दूरी के लिए सामान्य दर पर प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

(ख) उप-विनियम (3), के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) 1 अप्रैल, 2024 से स्थानांतरण पर अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि के पात्र होंगे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

तालिका

श्रेणी अथवा वेतनमान (1)	राशि (2)
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक (स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	₹.50000/-
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन (स्केल III तक के अधिकारी)	₹. 40000/-;

(ग) उप-विनियम (4) में, प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“बशर्ते कि 1 अप्रैल 2024 से, जहां बैंक द्वारा किसी अधिकारी को नई तैनाती के स्थान पर कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और जहां ऐसे अधिकारी को कार्यभार संभालने की प्रक्रिया में, उनके नियंत्रण से परे कारणों से अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है, सक्षम प्राधिकारी, नए स्थान पर ऐसे अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, परिस्थितियों के आधार पर या तो आवास और भोजन व्यय, अथवा 15 दिनों की अवधि के लिए विराम भत्ता या जब तक उन्हें क्वार्टर उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, जो भी पहले हो, देने पर विचार कर सकता है।”

20. उक्त विनियमों के विनियम 44 को, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“44 (1) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने अधिवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत हेतु पात्र होंगे:

बशर्ते कि, वे दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने अधिवास स्थान और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान पर निकटतम मार्ग से यात्रा कर सकते हैं:

(2) 1 अप्रैल, 2024 से, वैकल्पिक रूप में, एक अधिकारी, चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान, जैसा भी मामला हो, किसी भी समय एक विकल्प का प्रयोग करके अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (अधिवास के स्थान की यात्रा के अलावा) का समर्पण कर अपने छुट्टी यात्रा रियायत का नकदीकरण कर सकते हैं और यात्रा की अपनी पात्रता के अनुसार, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-I, मध्यम प्रबंधन श्रेणी- वेतनमान-II और मध्यम प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान-III के अधिकारी 5,500 किलोमीटर (एक तरफ की यात्रा) की दूरी तक तथा वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-IV और उससे ऊपर के अधिकारी 6,500 किलोमीटर (एक तरफ की यात्रा) रेल यात्रा के लिए पात्र किराए के समतुल्य राशि के नकदीकरण हेतु पात्र होंगे:

बशर्ते कि, अपनी छुट्टी यात्रा रियायत के नकदीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अधिकारी, नकदीकरण किए जाने वाले ब्लॉक के दौरान केवल एक बार अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावा कर सकते हैं और छुट्टी यात्रा रियायत के दौरान विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा छुट्टी किराया रियायत का नकदीकरण करते समय भी उपलब्ध है।

(3) एक अधिकारी जिस माध्यम और श्रेणी से सामान्यतः स्थानांतरण पर यात्रा हेतु पात्र होते हैं, उसी माध्यम से छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकते हैं और अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने से संबंधित अन्य नियम व शर्तें बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अधीन होंगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत के दौरान सबसे कम किराया इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने के लिए पात्र होंगे, ऐसे मामले में वास्तविक किराया या तय की गई दूरी के लिए रेल एसी प्रथम श्रेणी का किराया, इसमें से जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी और 500 किलोमीटर से कम दूरी होने पर छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के दौरान यही नियम मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारी पर भी लागू होंगे।"

(4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेते हैं, तो उन्हें एक बार में अधिकतम 30 दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी को समर्पित करने और नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है या उन्हें दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर और दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करते समय, प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिन या एक ब्लॉक में तीस दिन की विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है और छुट्टी के नकदीकरण हेतु उस महीने के लिए देय सभी परिलब्धियाँ स्वीकार्य होंगी, जिस दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लिया गया है:

बशर्ते कि, अधिकारी के विकल्प पर प्रधान मंत्री राहत कोष में दान के लिए एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी जोकि उनके द्वारा इस आशय का एक पत्र बैंक को देने और निधि में राशि भेजने के लिए प्राधिकृत करने के अधीन होगी।

(5) छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ स्वतंत्र रूप से उठाया जा सकता है, जहां पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हैं।

(6) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए, अवकाश यात्रा रियायत गुवाहाटी से शुरू होगी तथा उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक का पात्र रेल किराया अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा।

(7) इसी प्रकार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से चेन्नै अथवा कोलकाता, लक्ष्मीपुर से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर में दूर-दराज के क्षेत्रों की शाखाएं या कोई अन्य क्षेत्र जो सीधे रेल से नहीं जुड़े हैं, के लिए पात्र किराया अवकाश यात्रा रियायत के अंतर्गत इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक सामान्य पात्रता के अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(8) ऐसे अनुरक्षक को अवकाश यात्रा रियायत सुविधा दी जाएगी जो बैंचमार्क विकलांग अधिकारी के साथ यात्रा पर जाते हैं, जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः-

- (क) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाए।
- (ख) अधिकारी की शारीरिक विकलांगता की प्रकृति ऐसी है कि उसे यात्रा के लिए अनुरक्षक की आवश्यकता है। संदेह की स्थिति में, विभागाध्यक्ष अथवा नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा।
- (ग) ऐसे बैंचमार्क विकलांग अधिकारी के साथ जाने के लिए कोई वयस्क पारिवारिक सदस्य आश्रित के रूप में नहीं हैं।
- (घ) ऐसे बैंचमार्क विकलांग अधिकारी और अनुरक्षक द्वारा रेल अथवा बस किराए में छूट, यदि कोई हो, का लाभ लिया जाएगा, जैसा कि ऐसे मामलों में रेलवे अथवा राज्य सड़क मार्ग प्राधिकारियों द्वारा दिया जा सकता है।
- (ङ) कोई अन्य व्यक्ति, जो आश्रित के रूप में छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र हैं, ऐसे व्यक्ति विकलांग अधिकारी के साथ यात्रा पर नहीं जाते हैं।
- (9) जब किसी अधिकारी ने छुट्टी यात्रा रियायत अथवा छुट्टी के लिए पहले से आवेदन किया है और टिकट बुकिंग के बाद प्रबंधन द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को अस्वीकार या स्थगित कर दिया जाता है, तो रद्दीकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।
- (10) जब किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत अथवा छुट्टी के लिए आवेदन किया है तथा उन्हें मंजूरी दी गई है लेकिन ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है, तो तत्काल अथवा प्रीमियम तत्काल के अंतर्गत खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

21. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची
[विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें]

नवंबर, 2022 के पहले दिन से, एक अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ता के लिए तब तक पात्र होंगे जब तक कि उन्हें नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट किए अनुसार पूर्ण या आंशिक रूप से वापस लिया या संशोधित नहीं किया जाता है, अर्थात्:

तालिका
विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र. सं.	स्थान	भत्ता (रु.)	
		वेतन रु.48,481/- से कम	वेतन रु.48,481/- से अधिक
1	मिजोरम		
	क) चिंपटुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई टाउन से 25 कि.मी. से आगे के क्षेत्रों	4100	5300
	ख) संपूर्ण लुंगलेई जिला - लुंगलेई शहर से 25 किमी से आगे के क्षेत्रों को (छोड़कर)	4100	5300
	ग) संपूर्ण आइजोल जिला	2700	3400

2	नागालैंड	4100	5300
3	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
	क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार और नारकोडम द्वीप समूह	4100	5300
	ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4100	5300
4	सिक्किम	4100	5300
5	लक्षद्वीप समूह	4100	5300
6	असम	1000	1200
7	मेघालय	1000	1200
8	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	2700	3400
9	मणिपुर	2700	3400
10	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	4100	5300
11 ए	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर		
	1) कटुआ जिला : नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मल्होडी	4100	5300
	2) उधमपुर जिला:		
	(2) (क) डूड़ बसंतगढ़, लैंडर भामाग इलाका, थाकराकोटे और नागोटो।	4100	5300
	(ख) नीचे (ग) में शामिल क्षेत्रों के अलावा माहौर तहसील के सभी क्षेत्र।	4100	5300
	(ग) कम्बन साइड से गोएल तक के क्षेत्र और मोहरे तहसील में किआसी साइड से अरनस तक के क्षेत्र।	4100	5300
	(3) डोडा जिला:	4100	5300
	कश्मीर तहसील में पाडर और नियाबत नौगाम के इलाके		
	(4) बारामूला जिला		
	(क) संपूर्ण गुरेज-निरबत, तांगदार उप-मंडल और केरान इलाका	4100	5300
	(ख) माद्हिल	4100	5300
	(5) पुंछ और राजौरी जिला:	2700	3400
	पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र, दो जिलों में पुंछ और राजौरी और सुंदरबनी और अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर		
	(6) क्षेत्र जो ऊपर (1) से (5) तक में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं या वे स्थान जिन्हें राज्य सरकार ने अपने स्वयं के	2700	3400

	कर्मचारियों हेतु समय-समय पर सीमा भत्ता के लिए अर्हक घोषित किया जा सकता है।		
--	--	--	--

11 बी	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाखः लह जिला: नोयामा और नोब्रे जांस्कर जिले के अन्य सभी स्थान	4100	5300
12	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चंबा जिला		
	(क) पांगी तहसील, भरमौर तहसील के निम्न पंचायतें और गांवः पंचायतः बडगांव, बाजोल, देओल कुगती, नयागाम और टुंडा, गांवः ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी	4100	5300
	(ख) भरमौर तहसील, उपरोक्त (क) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर।	4100	5300
	(ग) भटियात तहसील में झंडरु पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (मुख्य बानीखेत सहित)	2700	3400
	(2) किन्नौर जिलाः		
	(क) असरंग, चितकुल और हांगो कुनो/ चारंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर छोटा खंबा, नाथपा और रूपी, पूह उप-मंडल की ग्राम पंचायतें शामिल हैं।	4100	5300
	(ख) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला।	4100	5300
	(3) कुल्लू जिलाः		
	(क) निरमंड तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा की ग्राम पंचायतें शामिल हैं	4100	5300
	(ख) बाहरी-सराज (निरमंड तहसील में बुरो और जकात-खाना के गांव छोड़कर) तथा बाहरी सराज क्षेत्र और पंडरबीस के परगना को छोड़कर पूरा जिला, किंतु निरमंड तहसील के जगत-खाना और बुरो गांव सहित।।	2700	3400
	(4) लाहौल और स्पीति जिलाः लाहौल और स्पीति का पूरा क्षेत्र	4100	5300
	(5) शिमला जिलाः		
	(क) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदना, सरपारा	4100	5300

	और चांदी-बरांडा की पंचायतें शामिल हैं।		
	(ख) डोडरा-कवार तहसील, रामपुर में डारकली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और परगना सराहन की मुनीश, गोरी चाईबीस।	4100	5300
	(ग) (I) चौपाल तहसील (i) परगना सराहन की घोरी, पंजगांव, पटसनौ, नौविस और तीन कोटी (ii) तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, (iii) परगना बाराबीस, (iv) रामपुर तहसील के रामपुर परगना के कस्बा रामपुर और घोरी नोग, (II) शिमला टाउन और उसके उपनगर (छल्ली, जाटोग, कसुमटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)।	2700	3400

	(6) कांगड़ा जिला:		
	(क) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	4100	5300
	(I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला टाउन और निम्नलिखित कार्यालय नगरपालिका सीमा से बाहर अवस्थित है लेकिन धर्मशाला टाउन में शामिल हैं – (क) महिला आईटीआई, दारी, (ख) मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, (ग) बाल कल्याण और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस, सकोह, (घ) सीआरएसएफ ऑफिस लोअर सकोह, (ड) कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, (च) एचआरटीसी कार्यशाला, सदर, (छ) क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दारी, (ज) वन निगम कार्यालय, शामनगर, (झ) चाय फैक्टरी, दारी, (ज) आईपीएच उप-मंडल, दारी, ट) बंदोबस्त कार्यालय, शामनगर, (ठ) बिनवा परियोजना, शामनगर। (II) पालमपुर टाउन, पालमपुर में एचपीकेवीवी कैंपस सहित और निम्नलिखित कार्यालय जो इसकी नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित हैं, लेकिन पालमपुर टाउन में शामिल हैं – क) एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, ख) पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनुरी, ग) रेशम उत्पादन कार्यालय/भारत-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला, (घ) विद्युत उप-मंडल, लोहना, (ङ) डी.पी.ओ. निगम, बुंदला,	2700	3400

	(च) इलेक्ट्रिकल एचर्चईएसई डिवीजन, घुगगरा		
	(7) मंडी जिला:		
	जोगिन्दरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील की पंचायतें - बगरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गटू, गरियास, जंजैहली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कलवान, खोलानल, लोठ, सिलीबागी, सोमाचन, तछधार, ताची, थाना, धरमपुर प्रखंड की निम्नलिखित पंचायतें : बिंगा, कमला, सकलाना, तान्यार और तारखोला, करसोग तहसील की पंचायतें-बालिधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, महूदी, मांज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें- बोही, बटवारा, धनयारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा।	2700	3400
	(8) सिरमौर जिला: क) निम्न स्थानों की पंचायतें	2700	3400
	i) बानी, बखाली (पाछड तहसील), ii) भारोग भनेरी (पोंटा तहसील), iii) बिडला (नाहन तहसील), iv) डिब्बर (पाछड तहसील) और v) थाना कसोगा (नाहन तहसील) और		

	ख) थांसगिरी ट्रैक्ट		
	(9) सोलन जिला: मंगल पंचायत	2700	3400
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं।	1000	1200
13	उत्तराखण्ड : चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चम्पावत जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4100	5300
14	पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भानातुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), ज़िंगखाली, सजनाखाली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पाथर प्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सिकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुशिघाटा (कुलटी)	1000	1200

के. राजेश कुमार, महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन

[विज्ञापन-III/4/असा./128/2025-26]

नोट:- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संसोधित किए गए, अर्थात्:-

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	दिनांक, जब आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई
1.	-----	07.12.1987	26.12.1987
2.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	05.05.1997	17.05.1997
3.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर /3169/2001	19.05.2001	16.06.2001
4.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर /853/2003	11.02.2003	15.03.2003
5.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर /2053/2006	21.03.2006	07.04.2006
6.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर /5207/2006	30.05.2008	05.06.2008
7.	एएक्स1/एसटी/ओएसआर/1324/2017-18	01.03.2018	14.03.2018
8.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/1325/2021-22	07.12.2021	14.12.2021
9.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/119/2024-25	04.12.2024	04.12.2024

विवरणात्मक ज्ञापन

विनियमों, जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर संयुक्त नोटों की सहमत शर्तों और नियमों के अनुसार सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी एशोसिएशनों के बीच हस्ताक्षरित हैं। अतः ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

BANK OF MAHARASHTRA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2025.

F.NO.:AX1/ST/OSR/01/2025-26.— In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Maharashtra, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Bank of Maharashtra (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, —
 - (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(f) “family”, in relation to an officer employee for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, means —

 - (i) the spouse of the officer;
 - (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
 - (iii) wholly dependent physically or mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;
 - (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
 - (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and
 - (vi) parents wholly dependent on the officer;

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to however fulfilling the income criteria for dependent.

Explanation 1.— The expression “wholly dependent family member” shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

Explanation 2.—For the purposes of medical expenses reimbursement scheme and Leave Fare Concession, for all officer employees, that is, male or female, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered and the officer employee shall have the choice to substitute either of the dependents, or both, once in a calendar year.

Explanation 3.— This definition shall be effective from the 1st day April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st day of November, 2024.

3. In regulation 4 of the said regulations, —

- (a) the *Explanation* to sub-regulation 7 shall be omitted;
- (b) for sub-regulations (8) and (9), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(8) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.156500 – 4340/4 – 173860

Scale VI = Rs.140500 – 4000/4 – 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 – 135020

Scale IV = Rs.102300 – 2980/4 – 114220 – 3360/2 – 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.85920 – 2680/5 – 99320 – 2980/2 – 105280

Scale II = Rs.64820 – 2340/1 – 67160 – 2680/10 – 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.48480 – 2000/7 – 62480 – 2340/2 – 67160 – 2680/7 – 85920.

Explanation.— Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on the 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(9) The scale of pay for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Top Executive Grade Scale VIII = Rs.253000 – 9000/4 – 289000.

(10) On and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V-10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII -11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(11) On and from the 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VIII - 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(12) On and from the 1st day of November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale II – III - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(13) The Special Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Special Allowance Scale VIII = 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to in sub-regulations (10) to (13) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (N P S), Provident Fund and Gratuity”.

(14) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.’.

4. In regulation 5 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (8) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following, namely:—

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (8) and (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clauses (c) and (d) below, subject to their crossing the efficiency bar;

(c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher

Scale, shall be eligible for seven stagnation increment/s, for every two completed years of service, of which the first two shall be Rs. 2680/- each and the next five shall be of Rs. 2980/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments each of Rs. 2980/- for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments, for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs.2980/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs.3360/- each:

Provided that the officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments, for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs.3360/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs.3680/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs.4000/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

- (h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments, for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs.4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs.4340/-:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs.4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs.4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs.4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

- (i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs.4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later.

Note: The increment/s as mentioned in clauses (a) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation. — Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

(b) in sub-regulation (2), —

(i) before the *Explanation*, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the 1st November, 2022, officers completing CAIIB or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers’ Examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers’ examination (CAIIB-I):

Provided further that officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed CAIIB or CAIIB II shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing CAIIB or CAIIB II, whichever is later:

Provided also that in case where an officer, as on the 8th March, 2024, has already acquired or acquires JAIIB or CAIIB-I or CAIIB (CAIIB-II) after reaching the maximum of the scale of pay (in case of JAIIB or CAIIB), or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay [in case of CAIIB (CAIIB-II)], and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.”.

(ii) in the *Explanation*, after clause (h), and before the Note the following clause shall be inserted, namely:—

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely:—

Table

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers (JAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part-I (CAIIB-I)	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale.
--	---

Those who have passed Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II)	(a) Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale; (b) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; and (c) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale:
---	---

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers(either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.”;

(iii) in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(vi) Officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and drawing Professional Qualification Pay -II shall be eligible for Professional Qualification Pay -III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) Officers who have completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.

(viii) Officers in Scale VIII shall not be eligible for Professional Qualification Pay and the same shall not form part of payslip components.”;

(c) in sub-regulation (3), —

(i) the Note after clause (g) shall be omitted;

(ii) after clause (g), the following shall be inserted, namely:—

“(h) On and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service: —

Table

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 1st November 2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663;

(i) Other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale – VIII, shall be at the rates given in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service: —

Table

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where Bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
9000	669	9669.

Note:

- (a) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers employees who are provided with bank's accommodation.
- (b) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table under clause (h) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub- regulations (2),(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;
- (c) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.
- (d) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of professional qualification pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and

second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released as on the 1st November, 2000.

(e) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(f) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale;

5. For regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

“7. Categorisation on appointed date.— Subject to the provisions of regulation 6, the various posts of officers in the Bank on the appointed date shall be categorised as specified in the Table below:

Table

Posts	Grade or Scale in which placed
(1)	(2)
Chief General Manager	Top Executive Grade – Scale VIII
General Manager	Top Executive Grade – Scale VII
Deputy General Manager	Top Executive Grade – Scale VI
Assistant General Manager	Senior Management Grade – Scale V
Chief Manager	Senior Management Grade – Scale IV
Senior Manager	Middle Management Grade – Scale III
Manager	Middle Management Grade – Scale II
Deputy Manager	Junior Management Grade – Scale I:

Provided that any difficulties and anomalies arising out of the above categorisation, shall be referred to a committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such other person or persons as may be appointed by the Central Government for this purpose, for its decision.”.

6. In regulation 21 of the said regulations, —

(a) In sub-regulation (6), in the *Explanation*, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), and (h) to the *Explanation* in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”;

(b) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(8) On and from the 1st November, 2022, —

Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index;

- (a) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01% change in Dearness Allowance on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;
- (b) the change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1st February based on the following, namely:—

Dearness Allowance release date	Quarterly average of CPI points of the months	Applicable for the month
1 st May	January, February and March	May, June and July
1 st August	April, May and June	August, September and October
1 st November	July, August and September	November, December and January
1 st February	October, November and December	February, March and April;

- (c) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;
- (d) while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.”.

7. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

‘(1) On and from the 1st November, 2022, —

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:

Table

Place of work (1)	House Rent Allowance (2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0% of Pay
(iii) Other places	8.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note:- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.'

8. In regulation 23 of the said regulations, —

(a) for sub regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

"(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable.

Table

Places (1)	Rate (2)
(i) Places in Area 1 and above and in the State of Goa	Rs. 2300/- per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900/- per month.

(2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both.

Provided further that of such higher of the two allowances is less than the aggregate of Special Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the officer on 31st December 1989 then such difference shall be protected as personal allowance till such time the officer remains at that place.”;

(b) for sub regulations (4), (5), (6) and (7), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(4) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum up to two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank, where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month:

Provided further that where an officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major A class cities where the distance of such deputation is 20 kms and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as mentioned in sub-regulation (4) of regulation 41.

(6) On and from the 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an Officiating Allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

(7) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.”;

(c) for sub-regulations (10), (11), (12) and (13) the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(10) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the Table below, namely:—

Table

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month.

(11) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs.850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: The Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme (NPS), Provident Fund and Gratuity.

(12) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance which shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme (NPS), Provident Fund and Gratuity.

(13) (a) From the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive (PLI) shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters:

(i) Current Account Savings Account - CASA (ii) Non-Performing Assets - NPA (iii) Special Mention Accounts - SMA (iv) Non – Interest Income - NII (v) Total Business (vi) Profitability (vii) Return on Assets - ROA or Return on Equity - ROE (viii) Government Schemes.

(b) The Performance Linked Incentive (PLI) amount shall be payable in 0-15 (max) number of days of pay (Basic + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a).”.

9. In regulation 24 of the said regulations,

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength own certificate of the officer of having

incurred such expenditure, supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:—

Table

Grade (1)	Maximum limit of reimbursement (2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less.

Note 1: - An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note 2: - For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2022 and December, 2022.”;

(b) after sub-regulation (3), following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) All officer employees shall also be eligible for reimbursement of Rs.500/- per year towards eye check-up.”.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), on and from the 1st November, 2022, it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2022, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the officer, the Sanctioning Authority shall record the reasons for the same in writing.”.

12. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half- a day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying 24 hours in advance:

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”.

13. In regulation 33 of the said regulations, —

(a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(4) On and from the 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April, 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty-five days:

Provided further that an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of 10 days shall be required for availing privilege leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.”;

(b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating privilege leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded.”.

14. In regulation 34 of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.”;

(b) after sub-regulation (5), following sub-regulations (6), (7) (8) and (9) shall be inserted, namely:—

“(6) On and from the 1st April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of 8 years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April, 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.”.

15. In regulation 36 of the said regulations, in sub-regulation (1), —

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—=

“(a) A female officer employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024, in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed by combining it with any other kind of leave except casual leave.”;

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) A female officer employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:—

(a) leave will be granted for adoption of only one child;

(b) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

- (c) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (d) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.”;

(c) after clause (e) following clause shall be inserted, namely:—

“(f) On and from the 1st April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(g) On and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.”.

16. For regulation 37A of the said regulations, following regulation shall be substituted, namely:—

“37A. Special casual leave and special leaves. - (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working, or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc,

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) With effect from the 1st April, 2024, the Principal Officer bearers of All India Officers' Unions or Associations shall be granted Special Leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1st April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry, may avail one day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

17. After regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

‘37B. Bereavement leave.- An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (Spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays shall form part of the bereavement leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of 15 days of the demise.

Provided also that the said leave shall not be considered as “active service” for the purpose of calculation of “privilege leave.”.

18. In regulation 41 of the said regulations,—

a. for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

(a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains [as mentioned in clause (a)] or by air (economy class):

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail, provided that the distance does not exceed 500 kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank’s vehicle;

(f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;

(g) an officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1: Goods and Services Tax charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

Note 2: In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.”;

b. in sub-regulation (4), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

‘4. (a) On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

Table

Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
	(1)	(2)		
	Metro Rs.	Major 'A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
Officers in Scale IV and V	3375	2925	2475	2150
Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation. — For the purpose of computing Halting allowance, “*per diem*” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “*per diem*” shall mean a period of not less than eight hours.

(b) An officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation Hotels of the corresponding star category set out in column (2) of the Table below:

Grade of Officers	Eligibility to stay
(1)	(2)
Scales- VI, VII and VIII	4* Hotel
Scales- IV and V	3* Hotel
Scales-II and III	2* Hotel (Non-AC)
Scale – I	1* Hotel (Non-AC)

Provided that the Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits specified above, in accordance with the guidelines of the Government.’.

19. In regulation 42 of the said regulations,—

(a) in sub-regulation (2), in clause (i), the following shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the 17th March, 2023, an officer on transfer shall be reimbursed his expenses for transportation of his personal effects from one place to another considering the fact that shipments are happening only through lorry, up to the following limits:

Pay Range	Where an officer has family	Where an officer has no family
48480-64820	3000 kgs or 3 Tonne	1500 kgs or 1.5 Tonne
64821 and above	12000 kgs or 12 Tonne	2500 kgs or 2.5 Tonne

The revised rates for reimbursement approved by the Board are as under:

Distance in kilometers	Revised rate in rupees per km
Up to 1000 kms	Rs. 5.90/-
Beyond 1000 kms	Rs. 4.25/-

Note 1: - The above rates shall be applicable on slab wise basis, that is, for the first 1000 kms, the rate applicable shall be Rs.5.90/- per km and thereafter it shall be Rs.4.25/- per km.

Note 2: - In case of officers transferred to shorter distances up to 300 kms, the reimbursement may be permitted up to 300 kms.

Note 3: - In case of officers transferred to and from hilly terrains, they may be reimbursed to the extent of two times of applicable rate for the distance covered in hilly terrain and at normal rate for the balance distance.”;

(b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:—

Table

Grade or Scale (1)	Amount (2)
Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III)	Rs.40000/-.”;

(c) in the sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that on and from the 1st April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and boarding charges, or Halting Allowance for a period of 15 days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.”.

20. For regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“44 (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I, while availing Leave Travel Concession, shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled, whichever is less, and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may, while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option, shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

(5) Leave Travel Concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.

(6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.

(7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel Concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(8) Leave Travel Concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to following conditions, namely:—

- a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;
- b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;
- c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;
- d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and
- e) any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.

(9) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.

(10) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.”

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 23]

On and from the 1st day of November, 2022, an officer shall be eligible for Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

Table
Special Area Allowance

Sl No.	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mizoram		
	(a) Chimgupiui District and areas beyond 25 kms from Lunglei Town in Lunglei District.	4100	5300
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms from Lunglei town	4100	5300
	(c) Entire Aizawl District	2700	3400

2	Nagaland	4100	5300
3	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	(b) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300
4	Sikkim	4100	5300
5	Lakshadweep Islands	4100	5300
6	Assam	1000	1200
7	Meghalaya	1000	1200
8	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except Difficult areas	2700	3400
9	Manipur	2700	3400
10	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except Difficult areas	4100	5300
11	A. - Union territory of Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) Udhampur District:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All Areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and Areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	(4) Baramulla District:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300
	(5) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	2700	3400
	(6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of 8 kms. from the Line of Actual Control (LOC) or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
	B.- Union territory of Ladakh: Leh District: Noyama and Nobre Zanskar All other places in the District	4100	5300

12	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and Villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet Proper)	2700	3400
	(2) Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats; 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi; Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above	4100	5300
	(b) Entire District other than areas included in (a) above	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	(5) Shimla District		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda	4100	5300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300
	c. (I) Chopal Tehsil (a) Ghoris, Panjaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan; (b) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area; (c) Pargana Barabis; and (d) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil; (II) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpton, Mashobra, Taradevi and Tutu)	2700	3400
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	4100	5300

	<p>(I) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Women's ITI, Dari, b) Mechanical Workshop, Ramnagar, c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, d) CRSF Office at lower Sakoh, e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, f) HRTC Workshop, Sadher, g) Zonal Malaria Office, Dari, h) Forest Corporation Office, Shamnagar, i) Tea Factory, Dari, j) I.P.H. Sub- Division, Dari k) Settlement Office, Shamnagar, l) Binwa Project, Shamnagar, <p>(II) Palampur Town, including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, b) Cattle Development Office or Jersey Farm, Banuri, c) Sericulture Office or Indo-German Agriculture Workshop or HPPWD Division, Bundla, d) Electrical Sub-Division, Lohna, e) D.P.O. Corporation, Bundla, f) Electrical HPSE Division, Ghuggar 	2700	3400
	(7) Mandi District:		
	<p>Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana,</p> <p>Following Panchayats of Dharampur Block:</p> <p>Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah,</p> <p>Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban,</p> <p>Panchayats of Sundernagar Tehsil –</p> <p>Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja</p>	2700	3400
	<p>(8) Sirmaur District:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Following Panchayats of <ul style="list-style-type: none"> (i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil); (ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil); (iii) Birla (Nahan Tehsil); (iv) Dibber (Pachhad Tehsil); and 	2700	3400

	(v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil); (b) Thansgiri Tract.		
	(9) Solan District: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts	4100	5300
14	West Bengal: South 24 Parganas District Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatsh Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1200.”.

K. RAJESH KUMAR , General Manager, Human Resources Management
[ADVT.-III/4/Exty./128/2025-26]

Note: The Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette of India and subsequently amended *vide* the following notifications published in the Gazette of India, Part III, section 4, namely:—

Serial number	Notification number	Notification date	Date on which published in the Official Gazette
1.	-----	07.12.1987	26.12.1987
2.	AX-1/ST/OSR/14046/96	05.05.1997	17.05.1997
3.	AX-1/ST/OSR/3169/2001	19.05.2001	16.06.2001
4.	AX-1/ST/OSR/853/2003	11.02.2003	15.03.2003
5.	AX-1/ST/OSR/2053/2006	21.03.2006	07.04.2006
6.	AX-1/ST/OSR/5207/2006	30.05.2008	05.06.2008
7.	AX-1/ST/OSR/1324/2017-18	01.03.2018	14.03.2018
8.	AX1/ST/OSR/1325/2021-22	07.12.2021	14.12.2021
9.	AX1/ST/OSR/119/2024-25	04.12.2024	04.12.2024

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.